कोरोना कूटनीति

लेखक- सी. राजा मोहन (निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

17 मार्च, 2020

" कोरोना वायरस संकट वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है और राष्ट्रों के बीच नए समीकरणों का कारण बन सकता है।"

यदि कोरोना वायरस संकट से निपटने के संभावित संयुक्त प्रयास में दक्षिण एशियाई नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा में चीन नहीं आता तो यह आश्चर्य की बात होती। पिछले दिसंबर से शुरू हुए संकट के बाद से चीन काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह उपमहाद्वीप के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में पहले से कहीं अधिक बड़ा प्रतीत हो रहा है।

यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि डॉ. जफर मिर्जा ने चीन को कोरोना वायरस संकट पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग से जोड़ने के लिए चुना। मिर्जा ने प्रधानमंत्री इमरान खान के बदले बैठक में भाग लिया, जो इस क्षेत्र के एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस बातचीत में भाग नहीं लिया। जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन पर मिर्जा की टिप्पणियों ने जितना व्यापक रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया, उतना चीन के बारे में उनका संक्षिप्त बयान कारगार साबित नही हुआ।

मिर्जा ने दक्षिण एशिया को वायरस के प्रसार को रोकने में चीन के अनुभव से सीखने को सही बताया। उन्होंने अपने सहयोगियों को यह भी याद दिलाया कि चीन सार्क समूह का एक पर्यवेक्षक देश है। देखा जाए तो सार्क में कई पर्यवेक्षक देश शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और ईरान शामिल हैं, जो सभी अपने-अपने तरीकों से कोरोना वायरस संकट के वैश्विक प्रसार से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मिर्जा ने केवल चीन पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखा।

COVID-19 आपातकालीन फंड

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कथन को चरितार्थ करने की दिशा में एक मजबूत पहल किया है। दरअसल, COVID-19 के बढ़ते वैश्विक प्रसार को रोकने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्क नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित किया।

'COVID-19 आपातकालीन फंड' में जमा धनराशी के संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए प्रधानमत्री ने कहा है कि इसमें डाली जाने वाली धनराशी का उपयोग तात्कालिक कदमों के लिए हम में से कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। इस फंड के संदर्भ में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा की इस फंड में हम सभी का योगदान स्वेच्छा पर आधारित हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत की तरफ से इस फंड के लिए 10 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक पेशकश की शुरुआत की जा सकता है।

इस संबोधन में एशिया महाद्वीप में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लगभग सभी उपायों पर चर्चा हुई।

इस कॉन्फ्रेंस में भारत ने यह स्पष्ट किया है कि हमने संभावित वायरस वाहकों और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए एक सर्वेलेंस पोर्टल की स्थापना की है, जिसे हम सार्क भागीदारों के साथ इस रोग निगरानी सॉफ्टवेयर को साझा कर सकते हैं और इसके उपयोग का प्रशिक्षण भी दे सकते हैं।

साथ ही प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने से रोकने के लिए विशेषज्ञों से यह अपील की है कि COVID-19 के दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों पर और मंथन करें जिससे हम अपने आंतरिक व्यापार और हमारी स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को इसके प्रभाव से कैसे और किस प्रकार अलग कर सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान की गहरी रणनीतिक साझेदारी ने कोरोनो वायरस संकट के लिए इस्लामाबाद की प्रतिक्रिया को परिभाषित किया है। जहाँ एक तरफ उपमहाद्वीप के अधिकांश देशों ने वुहान में फंसी अपनी छात्र आबादी को निकालने के लिए जी तोड़ कोशिश की, वहीं पाकिस्तान ऐसा करने में अनिच्छुक दिखा।

जैसा कि बीजिंग ने "चीन को अलग करने" की कोशिश के लिए अन्य देशों की आलोचना की, इस्लामाबाद बीजिंग के साथ एकजुटता से चट्टान की तरह खड़ा रहा। इसी तरह के एकजुटता का प्रदर्शन करने वाला एक अन्य देश कंबोडिया भी था, जिसके राष्ट्रपति ने चीनी नेतृत्व के साथ खड़े होने के लिए इस संकट के दौरान भी बीजिंग की यात्रा की। चीन के अधिकांश पर्यवेक्षक पाकिस्तान और कंबोडिया को बीजिंग के विकासशील देशों में केवल "सहयोगी" के रूप में नामित करेंगे।

सार्क (SAARC)

8 दिसंबर, 1985 में स्थापित सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों एक का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है जिसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है।

जहाँ तक इसके सदस्यों का सवाल है तो इसमें भारत, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

हालाँकि शुरुआती चरण में इसमें कुल सात सदस्य थे, किन्तु सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसमें आठवें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था।

जहाँ एक तरफ बीजिंग एकजुटता के सार्वजनिक प्रदर्शन को महत्त्व देता है, वहीं दूसरी तरफ इसमें अभी भी कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। जैसा कि जनवरी और फरवरी में वुहान और हुबेई प्रांत में संकट आने पर इसकी राजनीतिक रक्षात्मक थी, वहीं अब यह आक्रामक हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसने अपने देश में महामारी पर नियंत्रण पा लिया, तो बीजिंग ने संकट पर अपने विचार को बदलना शुरू कर दिया।

बीजिंग के प्रयास में तीन विषय हावी हैं। इसमें से पहला घरेलू राजनीति से संबंधित है और यह वायरस के खिलाफ अब "सफल युद्ध" में "नेता" शी जिनपिंग को "नायक" के रूप में पेश करने के बारे में है। चूँकि पिछले दो महीनों के दौरान कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या (अब 3,200 से ऊपर है) तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अटकलें लगाई जाने लगी कि शी के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी पर राजनीतिक संकट मंडराने लगे हैं, लेकिन शी ने आलोचकों और असंतुष्टों पर कड़ा प्रहार करते हुए (कम से कम अभी के लिए) सब को चुप करा दिया।

चीन के प्रयास का दूसरा विषय उस धारणा का मुकाबला करना है जिससे देश में वायरस उत्पन्न हुई थी। बीजिंग इसे "चाइना वायरस" या "वुहान वायरस" कहने पर कड़ी आपत्ति जता रहा है। इसने संकट का जवाब देने में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआती विफलताओं की आलोचनाओं को खारिज कर दिया है और अब चीनी अनुभव से सीखने में पश्चिमी अक्षमता पर हमला करने की बात दोहराई है। वुहान में वायरस लाने वाली अमेरिकी सेना के बारे में चीनी प्रवक्ताओं ने भी षड्यंत्रकारी सिद्धांतों का विरोध किया है।

चीनी रणनीति का तीसरा विषय कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण पाने में वैश्विक नेतृत्व का दावा करना है। ईरान और इटली (दोनों देश सबसे अधिक प्रभावित हैं) को चिकित्सा सहायता भेजकर बीजिंग तर्क दे रहा है कि यह वैश्विक संकट के समाधान का हिस्सा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि ने सभी सदस्य देशों को लिखा है कि वे वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दें और इस संकट के कारण शुरू हुई आर्थिक अव्यवस्था की बड़ी समस्याओं का समाधान करें।

राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाने वाली प्रमुख आपदाएँ पीड़ितों को अक्सर अपने विरोधी या दूर के देशों के साथ संघर्षरत रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए, भूकंप, बाढ़, सुनामी ने राष्ट्रों को एक साथ आने के लिए अक्सर मजबूर किया हैं। हालाँकि, कोरोना वायरस ने दुनिया की दो प्रमुख शक्तियों- अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने में कोई खास भूमिका नहीं निभाई।

तथाकथित "आपदा कूटनीति" का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि विपत्तियों से उत्पन्न राजनयिक संबंधों का उदय अल्पकालिक होते हैं। प्रकृति के प्रकोप के सामने मानव जाति के छोटेपन के प्रदर्शन के बीच, नेता एक दूसरे के बीच मतभेदों को सुलझाने के बारे में बड़ा सोचते हैं। लेकिन अध्ययन कहते हैं कि सामूहिक भलाई की सुविधा देने का वादा अक्सर राष्ट्रीय हित के संकीर्ण दायरे के कारण जल्दी से टूट जाता है।

जिस प्रकार विपत्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सकारात्मक सोच का भी प्रभाव समाप्त हो जाता है। हमने हाल के दशकों में उपमहाद्वीप में आई कई आपदाओं के लिए राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में इसे बार-बार देखा है।

क्या पाकिस्तान के साथ सहयोग और क्षेत्रीयता को फिर से जीवंत करने के लिए भारत के वर्तमान कूटनीतिक प्रयास पुराने गतिरोध के कारण असफल हैं? निराशावादियों का तर्क होगा कि पाकिस्तान के साथ सहयोग की तलाश एक मूर्खता है। आशावादियों का सुझाव है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और दिल्ली को भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध को फिर से शुरू करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे।

कई प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत कोरोना वायरस संकट वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है और राष्ट्रों के बीच नए समीकरणों का कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र के पुनर्गठन की नई संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार है? दिल्ली ने निश्चित रूप से पड़ोसियों के साथ बहुपक्षीय बातचीत को नवीनीकृत करने में एक महत्त्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। इसे अब उपमहाद्वीप के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बेहतर कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाल ही में कोरोना वायरस के मुद्दे पर सार्क देशों की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें चीन ने भाग नहीं लिया है।
2. कोरोना वायरस के प्रकोप ने भी चीन और अमेरिका के संबंध में सुधार नहीं किया है।
3. कोरोना पर सार्क की बैठक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्पन्न हुई है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:

1. Recently there was a meeting of SAARC countries on the crisis of Corona virus, in which China has not participated.
2. The outbreak of Corona virus has also not improved the relation of China and America.
3. The SAARC meeting on Corona was concluded through a video conferencing.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) 1 and 3

(c) 2 and 3 (d) All of the above

नोट : 16 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. कोरोना वायरस के प्रसार से लड़ने हेतु एक संयुक्त दक्षिण एशियाई मंच बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल भारत के लिए किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

How is Prime Minister Modi's initiative to create a United South Asian Platform to fight the spread of the corona virus is important for India? Comment. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।